खंड १४ नंबर १ जनवरी २०१८

आरआईएस डायरी

–अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

आसियान–भारत कनेक्टिविटी शिखर सम्मेलनः 21वीं सदी में एशिया के लिए डिजिटल और भौतिक संपर्कों की मजबूती पर विचार

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) के सहयोग से 11–12 दिसम्बर 2017 को नई दिल्ली में पहली बार आसियान–भारत कनेक्टिविटी शिखर सम्मेलन (एआईसीएस) का आयोजन किया। सम्मेलन का आयोजन आसियान–भारत संवाद साझेदारी के 25 साल पूरे होने के अवसर पर किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी पर विशेष जोर देते हुए कनेक्टिविटी के विभिन्न तरीकों या साधनों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करना और उनसे अवगत होना था। सीआईआई की अध्यक्ष सुश्री शोभना कमिनेनी ने स्वागत भाषण दिया और उद्घाटन सत्र का संचालन

शेष पृष्ठ 5 पर जारी.....

(बाएं से दाए): सुश्री अनिता प्रकाश, महानिदेशक, नीति विभाग, ईआरआईए; श्री रजत नाग, विशिष्ट फेलो, एनसीएईआर; वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान, निदेशक, राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन; श्री एम जे अकबर, माननीय विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार; श्री योजी फुरुई, औद्योगिक शोधकर्ता, जेट्रो इंडिया और अर्थव्यवस्था मंत्रालय, भारत में जापान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि; श्री रोनाल्ड बुतिओंग, निदेशक, दक्षिण एशिया, एशियाई विकास बैंक, फिलीपींस और डॉ. प्रबीर डे, समन्वयक, आसियान–भारत केन्द्र (एआईसी)।

पूर्वोत्तर भारत का विकास और भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति

आरआईएस, विदेश मंत्रालय, एफआईडीसी, फिक्की, और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि (आरजीवीएन) सोसायटी, गुवाहाटी, ने संयुक्त रूप से 24–25 अक्टूबर 2017 को असम के गुवाहाटी में क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी और गुवाहाटी स्थित आरजीवीएन सोसायटी के कार्यकारी निदेशक डॉ. अमिय शर्मा के परिचयात्मक आरंभिक भाषणों के साथ हुई। श्री नवीन वर्मा, सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने मुख्य भाषण तथा श्री आलोक डिमरी, संयुक्त सचिव (एमईआर), विदेश मंत्रालय ने विशेष भाषण दिये। प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती, विजिटिंग फेलो, आरआईएस, ने धन्यवाद ज्ञापन पेश किया।

श्री आलोक डिमरी, संयुक्त सचिव (एमईआर), विदेश मंत्रालय, उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

परामर्श के दौरान छह सत्रों का आयोजन किया गयाः पूर्वोत्तर और एक्ट–ईस्ट नीतियों के बीच तालमेल – औचित्य, तकनीकी; सीमा व्यापारः वर्तमान

शेष पृष्ठ 8 पर जारी.....

राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 2018 : उभरती विकास रणनीतियाँ

राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 2018, आरआईएस और एफआईडीसी द्वारा संयुक्त रूप से 28 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, ने स्वागत भाषण दिया। राजदूत अमर सिन्हा, विशिष्ट फेलो, आरआईएस, ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की और विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (यूएनपी), श्री रुद्रेंद्र टंडन, ने उद्घाटन भाषण दिया। श्री सेंट जॉन गोउल्ड, निदेशक, ब्रिटिश व्यापार और अर्थशास्त्र, भारत, ब्रिटिश उच्चायोग, ने विशेष भाषण दिया।

शेष पृष्ठ 10 पर जारी.....

श्री रुद्रेंद्र टंडन, संयुक्त सचिव (यूएनपी), विदेश मंत्रालय, उद्घाटन भाषण देते हुए।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एसटीआईपी) व्याख्यान

आरआईएस, टेरी, सीएसई, आईएचसी, सीईएफआईपीआरए, विज्ञान प्रसार, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज और स्प्रिंगर नेचर ने 21 दिसम्बर 2017 को नई दिल्ली में 'तरल नमक प्रौद्योगिकियों से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को पलटना' विषय पर चतुर्थ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एसटीआईपी) फोरम व्याख्यान का आयोजन किया। प्रो. फ्रैंक शू, प्रख्यात खगोल विज्ञानी और एकेडमी–स्प्रिंगर नेचर, चेयर प्रोफेसर, ने इस विषय पर श्रोतागण को संबोधित किया। डॉ. जयराम रमेश, सांसद (राज्य सभा), ने फोरम की अध्यक्षता की और मूल्यवान संकेतक सुझाए।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के परिचयात्मक व आरंभिक संबोधन से हुआ; श्री शिरीष गरुड़, सीनियर फेलो और निदेशक, टेरी, ने भी सम्बोधन किया।

प्रोफेसर शू ने अपने व्याख्यान में तरल नमक प्रौद्योगिकियों के संभावित उपयोगों के बारे में बताया और इसके साथ ही कहा कि भारत, में थोरियम का विशाल भंडार है, और

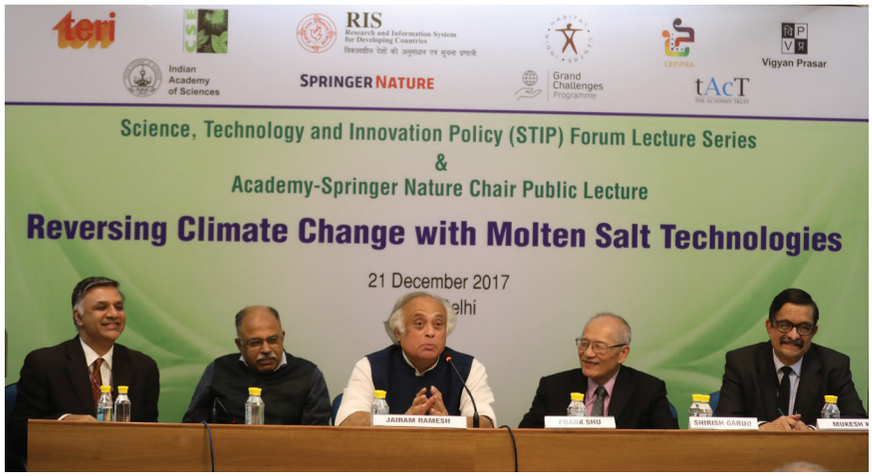

डॉ. जयराम रमेश, सांसद (राज्य सभा) (बाएं से तीसरे), व्याख्यान कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए।

उसका दोहन कर कम कार्बन उत्सर्जन के साथ ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। उन्होंने एनसीआर क्षेत्र में फसल–अवशेषों या पराली को जलाए जाने की समस्या को हल करने और फसल उत्पादकता बढ़ाने में तरल नमक (मोल्टन साल्ट) प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग से जुड़े एक दिलचस्प प्रयोग का भी उल्लेख किया।

डॉ. जयराम रमेश ने इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के प्रतिनिधियों से इस तरह के उपयोग की खूबियों का पता लगाने का अनुरोध किया। डॉ. मुकेश कुमार, निदेशक, इंडो–फ्रेंच सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवांस्ड रिसर्च, नई दिल्ली, ने धन्यवाद ज्ञापन किया। (इस व्याख्यान का वेबकास्ट पर सीधा प्रसारण भी किया गया था।)

दक्षिण एशिया में विकास वित्त और उभरते विकास अनुभव

आरआईएस ने 17–18 दिसंबर 2017 को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित कोवलम में 'दक्षिण एशिया में विकास वित्त और उभरते विकास अनुभवः दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए आगे की राह' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। विकास वित्त से जुड़े दक्षिण एशियाई अनुभव पर पहला सत्र आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के भाषण के साथ शुरू हुआ। प्रोफेसर मुस्तफिजूर रहमान, विशिष्ट फेलो, सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग (सीपीडी), ढाका, बांग्लादेश; प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस; प्रोफेसर मुकुल आशेर, प्रोफेसरियल फेलो, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और राजदूत ल्योंपो डैगो शेरिंग, भारत में भूटान के पूर्व राजदूत ने विकास वित्त से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रोफेसर मिलिंदो चक्रबर्ती, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

विशिष्ट प्रस्तुतियों पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर मुकुल आशेर ने की। श्री नजीर कबीरी, मंत्री के सलाहकार, वित्त मंत्रालय, अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य; डॉ. मुस्तफा के मुजेरी, कार्यकारी निदेशक, समावेशी वित्त एवं विकास संस्थान (आईएनएम), ढाका, बांग्लादेश (डॉ. सब्यसाची साहा, आरआईएस द्वारा प्रस्तुति); श्री इब्राहिम अमीर, पूर्व अर्थशास्त्री, मालदीव सेंट्रल बैंक, मालदीव; डॉ. रवींद्र पांडेय, सदस्य, निदेशक मंडल, रणनीतिक एवं सामाजिक–आर्थिक अनुसंधान संस्थान, नेपाल; श्री किथमिना हेवेज, अनुसंधान अधिकारी और सुश्री हरिनी वीरासेकेरा, अनुसंधान सहायक, नीतिगत अध्ययन संस्थान, श्रीलंका – (स्काइप द्वारा) मुख्य वक्ता थे। डॉ. अब्राहम जॉर्ज, निदेशक और प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस इस सत्र में हुई औपचारिक चर्चा के प्रमुख प्रतिभागी थे।

'दक्षिण एशिया में विकास वित्त और उभरते विकास अनुभवः दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए आगे की राह' पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागी।

माननीय प्रो. बिश्वंभर प्याकुरिइल, नेपाल के राजदूत, श्रीलंका ने 'आगे की राह' पर आयोजित तीसरे सत्र की अध्यक्षता की। प्रोफेसर सैकत सिन्हा रॉय, अर्थशास्त्र विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय; प्रोफेसर मुकुल आशेर, प्रोफेसरियल फेलो, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर; श्री नजीर कबीरी, मंत्री के सलाहकार, वित्त मंत्रालय, अफगानिस्तान का इस्लामी गणराज्य, इस अवसर पर मुख्य वक्ता थे।

इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 'उभरते विकास अनुभवः दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए आगे की राह' पर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से आरआईएस और एफआईडीसी द्वारा किया गया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने इस परिचर्चा का संचालन किया। प्रो. मुकुल आशेर; प्रोफेसर ई. हरिबाबू, भूतपूर्व उपकुलपति एवं समाजशास्त्र के प्रोफेसर, हैदराबाद विश्वविद्यालय; प्रोफेसर ए. दामोदरन, चेयर प्रोफेसर आईपीआर चेयर ऑन आईपी मैनेजमेंट (एमएचआरडी), अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरू; डॉ. बालाकृष्ण पिसुपति, पूर्व कुलपति, ट्रांस डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, बेंगलुरू; श्री उत्तमसिंह गुडुर, द्वितीय सचिव, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेश मंत्रालय, मॉरीशस; सुश्री गुलनाज अताबेईवा, अला–टू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बिश्केक, किर्गिस्तान; सुश्री कैमिला जर्दिम, इंटरनेशनल रिलेशंस इंस्टीट्यूट ऑफ पोन्तिफिशिया यूनिवर्सिडेड कैटोलिका डू रियो डी जनेरियो (पीयूसी–रियो), ब्राजील; श्री मार्टिंस सिल्वा, आर्टिकुलाकाओ सुल – दक्षिण दक्षिण सहयोग अनुसंधान एवं नीतिगत केंद्र, ब्राजील और श्री सियासंगा डिंगेला, नेल्सन मंडेला मेट्रोपॉलिटन यूनीवर्सिटी, दक्षिण अफ्रीका, इस अवसर पर विशिष्ट प्रतिभागी थे।

चौथा 'इंडियालिक्स' सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यशाला 2017

विज्ञान नीति में अध्ययन के लिए केंद्र, जेएनयू; आरआईएस एवं सीएसआईआरएनआईएसटीएडीएस ने नई दिल्ली में 2 से 4 नवंबर तक संयुक्त रूप से चौथे 'इंडियालिक्स' सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यशाला 2017 का आयोजन किया जिसका शीर्षक था 'सतत विकास के लिए नवाचार: दक्षिण एशिया में परिप्रेक्ष्य, नीतियां और प्रथाएं'।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो. एम जगदीश कुमार, कुलपति, जेएनयू, के भाषण के साथ हुआ। उद्घाटन सत्र में प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डीजी, आरआईएस, ने विशेष भाषण के जरिए परिचर्चा की शुरुआत की और इसके साथ ही उन्होंने उत्तरदायी अनुसंधान एवं नवाचार पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता भी की। प्रो. मम्मो मुची, त्शवेन यूनीवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका, ने उद्घाटन भाषण दिया।

इस सम्मेलन के दौरान दक्षिण एशियाई दृष्टिकोणों के संदर्भ में सतत विकास के लिए नवाचारों के स्वरूप, निर्धारकों एवं दिशा और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए तौर–तरीकों का पता लगाया गया। सम्मेलन के दौरान विचार–विमर्श मुख्यतः

सम्मेलन के एक सत्र में मौजूद प्रतिभागी।

सामाजिक–आर्थिक विकास और स्थायित्व के लिए नवाचार को बढ़ावा देने की राह में मौजूद चुनौतियों एवं अवसरों पर केंद्रित थे और इसके उप–विषय ये थे : टिकाऊ कृषि के लिए नवाचार; वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं एवं नवाचार प्रणालियां; स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन; जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन; शमन, एवं लचीलापन; महिला–पुरुष, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार; अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में नवाचार; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) के लिए संकेतक, आरएंडडी एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण; विश्वविद्यालय–उद्योग जुड़ाव; स्वास्थ्य सेवा एवं फार्मास्यूटिकल्स में नवाचार; विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) में आईपीआर, मानक तथा विनियम; प्रौद्योगिकी के लिए दूरदर्शिता एवं भविष्य और उत्तरदायी नवाचार। दक्षिण–एशियाई देशों के 100 से भी अधिक वक्ताओं ने इस सम्मेलन में सक्रियता रूप से भाग लिया।

सम्मेलन के दौरान भारत की एसएंडटी नीति बनाने एवं उसे विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रो. अशोक पार्थसारथी का सम्मान और अभिनंदन करने हेतु एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया। विस्तृत कार्यक्रम आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र

आरआईएस ने 22 दिसंबर 2017 को 'भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र' पर डॉ. बी प्रसाद सकलानी, प्रोफेसर, ऊर्जा और पर्यावरण विभाग, टेरी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, के एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने इस विषय पर विशेष अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रारंभिक चर्चाओं की शुरुआत की। प्रो. अमिताभ कुंडू, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस ने सत्र की अध्यक्षता की।

व्याख्यान के दौरान सौर ऊर्जा के उत्पादन एवं व्यापार से जुड़े विभिन्न प्रासंगिक पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान यह परिचर्चा संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास एवं

व्याख्यान कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागी।

वाणिज्यीकरण और अपस्ट्रीम सौर उत्पादन सुविधाओं से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर केंद्रित रही। इसके बाद प्रतिभागियों के साथ संवाद का दौर चला।

आसियान–भारत कनेक्टिविटी शिखर

पृष्ठ 1 से जारी.....

किया। जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त), माननीय विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार, ने विशेष भाषण दिया। माननीय फान टैम, उप मंत्री, वियतनाम का सूचना एवं संचार मंत्रालय, वियतनाम सरकार ने भी विशेष भाषण दिया। श्री नितिन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग और जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री, भारत सरकार, ने मुख्य भाषण दिया।

इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में एक उद्घाटन सत्र, एक विशेष पूर्ण, छह पूर्ण और चार समानांतर सत्र थे। इस सम्मेलन में आसियान के सदस्य देशों और भारत के सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं, निवेशकों, कारोबारी हस्तियों, व्यापार निकायों एवं संघों तथा उद्यमियों ने शिरकत की। भारत और आसियान देशों के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने उद्घाटन सत्र के अलावा एआईसीएस में संबोधन भी किया जिनमें श्री एम. जे. अकबर, माननीय विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार; श्री लिम चेन, निदेशक, आसियान सचिवालय, जकार्ता; श्री मनोज सिन्हा, माननीय संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार, और श्री पी.डी. राय, सांसद (लोकसभा), के अलावा श्री नितिन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री, भारत सरकार, प्रमुख थे।

(बाएं से दाएं): श्री पंकज टंडन, उपाध्यक्ष, टीएंडडी–सार्क, केईसी इंटरनेशनल; श्री प्रशांत अग्रवाल, जेएस (डीपीए–1), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार; श्री एस सेल्वाकुमार, जेएस (एबीसी), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री नदीम पांजेतन, सीजीएम – एलओसी ग्रुप, एक्जिम बैंक और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डीजी, आरआईएस 'कनेक्टिविटी का निर्माण करना : ऋण व्यवस्था' पर आयोजित पूर्ण सत्र के अवसर पर।

यह शिखर सम्मेलन भारत में आसियान और हिंद–प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने संबंधी भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भौतिक एवं डिजिटल परियोजनाओं के लिए भारत ने जो कनेक्टिविटी संदर्भ पहलें की हैं वे आसियान कनेक्टिविटी पर मास्टर प्लान (एमपीएसी) 2025 के रणनीतिक क्षेत्रों, विशेषकर टिकाऊ बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, डिजिटल नवाचार, निर्बाध लॉजिस्टिक्स, विनियामक उत्कृष्टता और लोगों की गतिशीलता के पूरक के तौर पर हैं।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने 'कनेक्टिविटी का निर्माण के लिए: ऋण व्यवस्था' पर आयोजित पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की और भारत की ऋण व्यवस्था के तहत कनेक्टिविटी की विभिन्न मौजूदा एवं प्रस्तावित परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने यह तथ्य भी दोहराया कि भारत एवं आसियान के बीच भौतिक तथा डिजिटल संपर्कों को बढ़ावा देने से, इस क्षेत्र में व्यापक विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

विकास सहयोग के प्रति दृष्टिकोण : नई साझेदारियों के लिए उभरती गुंजाइश

आरआईएस में 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग को सीखने–समझने' पर आयोजित आईटीईसी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में 13 नवंबर 2017 को एक पैनल परिचर्चा का आयोजन आरआईएस, नेस्ट और एफआईडीसी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का आरम्भ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के भाषण के साथ हुआ। इसकी अध्यक्षता राजदूत अमर सिन्हा, विशिष्ट फेलो, आरआईएस ने की। श्री गद्दाम धर्मेंद्र, संयुक्त सचिव (पीपीएंडआर), विदेश मंत्रालय; श्री यूरी अफानासीव, संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक एवं भारत में यूएनडीपी के प्रतिनिधि और श्री गैविन मैकगिलिवरे, प्रमुख, डीएफआईडी इंडिया, ब्रिटिश उच्चायोग, के साथ–साथ सुश्री इंद्राणी बागची, वरिष्ठ संपादक, द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, इस अवसर पर विशेष पैनलिस्ट थे।

भारतीय अर्थव्यवस्थाः विकास की संभावनायें

आरआईएस के प्रथम नीतिगत चर्चा सत्र में भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार, डॉ. सौम्य कांति घोष ने 6 अक्टूबर, 2017 को नई दिल्ली में भारतीय अर्थव्यवस्था की 'व्यापक तस्वीर' पर एक व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि भारत की व्यापार संबंधी पारम्परिक दिशा में ढांचागत बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अतः भारतीय व्यापार को अफ्रीकी देशों में नए बाजारों की तलाश करनी होंगी क्योंकि वहां फिलहाल जनसांख्यिकीय लाभांश अथवा आबादी के मामले में बेहतर स्थिति नजर आ रही है। हालांकि, भारत में आंतरिक ढांचागत समायोजन से न तो निर्यात के मोर्चे पर अपेक्षित प्रतिस्पर्धी क्षमता हासिल हुई है और न ही 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिल पाया है। चिंता का एक अतिरिक्त विषय नई प्रौद्योगिकियों का उद्भव है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), जिस वजह से भारत से होने वाले सेवा निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

2011 और वर्ष 2016 के बीच की ओईसीडी रैंकिंग के अनुसार भारत के साथ–साथ ब्रिटेन, पुर्तगाल और इटली भी अपने यहां भ्रष्टाचार के स्तर में कमी करने और सकारात्मक जीडीपी वृद्धि दर हासिल करने के प्रयासों में सफल हुए हैं। जिन देशों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जैसा कि ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल के आकलन से पता चला है, वहां जीडीपी वृद्धि दर घट गई है। यह भ्रष्टाचार विरोधी उपायों से हुए फायदों को दर्शाता है। जीएसटी जैसे अन्य ढांचागत सुधारों से इसे जोड़ते हुए डॉ. घोष ने कहा कि इस तरह के उपाय अर्थव्यवस्था की दक्षता एवं प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ा देते हैं और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक राजकोषीय स्थायित्व सुनिश्चित करते हैं।

आसियान–भारत साझेदारी में मजबूती

आसियान–भारत साझेदारी के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) ने आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल (एआईबीसी), एशिया पेसिफिक पाथवेज टू प्रोग्रेस फाउंडेशन, इंक., फिलीपींस; इंस्पेरॉन, फिलीपींस; न्यू एरा यूनीवर्सिटी, फिलीपींस; और फिलीपींस में भारत के दूतावास के सहयोग से 21 नवंबर 2017 को मनीला में पहली बार आसियान–भारत फोरम का आयोजन किया जिसका शीर्षक था 'फिलीपींस और भारतः आसियान–भारत साझेदारी को मजबूत बनाना।'

श्री जेम्स मानजनेरो, सीओओ, ईगल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ने स्वागत भाषण दिया। माननीय मैनुअल एंटोनियो जे. तीहानकी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के लिए अवर सचिव, विदेश मामलों का विभाग, फिलीपींस ने विशेष भाषण दिया। माननीय राजदूत जयदीप मजूमदार, फिलीपींस में भारत के राजदूत ने मुख्य भाषण दिया। डॉ. कार्लोस सी. तबुंदा, निदेशक, आसियान अध्ययन केन्द्र, न्यू एरा यूनीवर्सिटी (एनईयू) ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

फोरम को चार सत्रों में विभाजित किया गया था, ताकि पहले सत्र में आर्थिक सहयोग, राजनीतिक सामंजस्य एवं रणनीतिक साझेदारियों पर फिलीपींस के नजरिए से अवगत होकर भारत तथा फिलीपींस के संबंधों को मजबूत करने के मार्ग में मौजूद चुनौतियों एवं आगे की राह की पहचान की जा सके और इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा सके कि कैसे भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति ने तेज रफ्तार पकड़ी है, ताकि दूसरे सत्र में फिलीपींस पर विशेष ध्यान देते हुए आसियान–भारत संबंधों के व्यापार एवं कनेक्टिविटी पहलुओं का पता लगाया जा सके, और तीसरे सत्र में दोनों देशों की जनता के बीच आपसी जुड़ाव के साथ–साथ सांस्कृतिक संबंधों का भी अनुमोदन किया जा सके। एक विशेष सत्र भारत–फिलीपींस संबंधों के मार्ग की चुनौतियों पर चर्चा करने और आगे की राह पर रोशनी डालने के लिए भी आयोजित किया गया। डॉ. प्रबीर डे, समन्वयक, आरआईएस स्थित एआईसी और डॉ. कार्लोस तबुंडा जूनियर, निदेशक, आसियान अध्ययन केंद्र, एनईयू, ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

प्रथम आसियान–भारत फोरम में मौजूद प्रतिभागी।

दसवां दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन

दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन (एसएईएस) पिछले 10 वर्षों से दक्षिण एशिया में एक प्रमुख क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म रहा है। इस क्षेत्र में आरआईएस, नीतिगत अध्ययन संस्थान (आईपीएस), सतत विकास नीति संस्थान (एसडीपीआई), नीतिगत संवाद के लिए केंद्र (सीपीडी) और व्यापार, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण पर दक्षिण एशियाई चौकसी (एसएडब्ल्यूटीईई) सहित पांच अग्रणी प्रबुद्ध मंडलों (थिंक–टैंक) की एक संयुक्त पहल के रूप में एसएईएस ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण एवं सहयोग के स्वरूप, गुंजाइश तथा गति से संबंधित विभिन्न मुद्दों और दक्षिण एशियाई देशों के समक्ष पेश आ रहे समकालीन विकास मुद्दों, जैसे कि सामाजिक एवं आर्थिक मसलों पर हुए संवाद एवं बहस, को मोटे तौर पर कवर किया है। पिछले सम्मेलनों में सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर चर्चा करने के अलावा एसएईएस में नई और उभरती चुनौतियों जैसे कि वैश्विक आर्थिक मंदी 2008–09 से उत्पन्न वित्तीय नुकसान के जोखिमों, 'ब्रेक्जिट' के असर, क्षेत्रीय एकीकरण पहलों को लगे झटकों, जलवायु परिवर्तन के असर, डेटा माप में नवाचार पर सांख्यिकीय विश्लेषण, इत्यादि को सुदर्ण्ण बनाया गया है। एसएईएस के पिछले शिखर सम्मेलनों ने अग्रणी विचारकों, नीति निर्माताओं और प्रबुद्ध मंडलों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सरकारों, सिविल सोसायटी और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को विनिकिया है जिन्होंने अध्यक्षों, संचालकों, वक्ताओं और चर्चाकर्ताओं के रूप में बहुमूल्य योगदान दिया है। इस तरह के प्रत्येक पिछले सम्मेलनों में दक्षिण एशियाई एकीकरण एजेंडे पर जारी बहस में उल्लेखनीय मूल्यवर्द्धन प्रगति हुई है और संबंधित देशों के अधिक–से–अधिक लोगों के बीच बातचीत पर ध्यान केंद्रित करके दक्षिण एशियाई पहचान को प्रोत्साहित किया गया।

दसवां दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन (एसएईएस) 14 से 16 नवंबर 2017 तक काठमांडू में आयोजित किया गया था, जिसका केंद्रीय विषय था 'दक्षिण एशिया में समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना।' चार पूर्ण सत्रों एवं 14 समानांतर सत्रों में फैली परिचर्चाओं के दौरान वक्ताओं तथा चर्चाकर्ताओं ने सार्क की मौजूदा क्षेत्रीय एकीकरण पहलों और बीबीआईएन जैसी उप–क्षेत्रीय पहलों की ताकत पर गहन विचार–विमर्श किया और साथ ही उन्होंने साझा समृद्धि के विजन एवं उस सपने को साकार करने संबंधी रोडमैप के तत्वों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया। व्यापक क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करने के अलावा अंतिम पूर्ण सत्र में स्वर्गीय डॉ. समन केलेगामा को श्रद्धांजलि दी गई, जो दक्षिण एशिया के शोध एवं नीतिगत समुदायों के बीच एक प्रतिष्ठित हस्ती माने जाते थे और जिन्होंने दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय एकीकरण के लिए अथक प्रयास किए थे। यह शिखर सम्मेलन सामान्य रूप से सार्क के भविष्य पर और विशेष रूप से व्यापार, निवेश, व्यापार सुविधा और ऊर्जा सहयोग, एसडीजी सहित आर्थिक एकीकरण पर व्यापक एवं रचनात्मक चर्चा के लिए एक परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म साबित हुआ। आरआईएस भी 'एसएईएस' के आयोजन में राष्ट्रीय योजना आयोग, नेपाल सरकार; और एसएडब्ल्यूटीईई, काठमांडू, के साथ प्रमुख भागीदारों में से एक था। बौद्धिक जानकारियां देने और समन्वय संबंधी सहायता प्रदान करने के अलावा चार सदस्यीय संकाय दल ने शिखर सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डीजी, आरआईएस, ने दक्षिण एशिया में एसडीजी एवं समावेशी विकास पर एक प्रस्तुति दी और डॉ. प्रबीर डे, समन्वयक, आरआईएस स्थित एआईसी ने व्यापार में सुगमता, पारगमन और कनेक्टिविटी के मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा, डॉ. प्रियदर्शी दाश, रिसर्च एसोसिएट, आरआईएस भी व्यापार में सुगमता, पारगमन और कनेक्टिविटी पर आयोजित सत्र मे एक पैनलिस्ट के रूप में जुड़े। आरआईएस के श्री वैभव कौशिक ने भी एसएईएस में भाग लिया।

दसवें दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन में परिचर्चा प्रगति पर

विचार–विमर्श के दौरान प्रतिष्ठित प्रतिभागियों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि क्षेत्रीय सहयोग का औचित्य दुनिया भर में उत्पादन एवं व्यापार के बदलते स्वरूप और जलवायु परिवर्तन जैसी नई चुनौतियों के अनुरूप होना चाहिए। प्रतिभागियों ने क्षेत्रीय निकाय के ढांचे एवं निर्णय लेने के तौर–तरीकों में सुधार कर, सचिवालय को मजबूत कर एवं अन्य जगहों

शेष पृष्ठ 9 पर जारी.....

आसियान@50 और आसियान–इंडिया@25

आसियान–भारत साझेदारी के 25 साल और आसियान के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आरआईएस स्थित आसियान–भारत केन्द्र (एआईसी) ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के विदेश नीति अध्ययन संस्थान (आईएफपीएस) तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं विकास के अध्ययन के लिए केंद्र (सीएसआईआरडी) के सहयोग से 22 दिसंबर 2017 को कलकत्ता विश्वविद्यालय, अलीपुर कैंपस, कोलकाता में 'आसियान@50 और आसियान–इंडिया@25' पर सम्मेलन का आयोजन किया। प्रो. शांतनु चक्रबर्ती, आईएफपीएस, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने स्वागत भाषण दिया। उद्घाटन भाषण प्रो. हरि वासुदेवन ने दिया। राजदूत सरबजीत चक्रवर्ती ने विशेष भाषण दिया। इस सम्मेलन में पैनलिस्ट थे: श्री अंबरीश दासगुप्ता, इंट्यूएरी कंसल्टिंग के संस्थापक निदेशक, लेफ्टिनेंट जनरल जॉन मुखर्जी; डॉ. इशानी नस्कर, प्रोफेसर, रबींद्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता; मेजर जनरल अरुण राय, सीएनआरईएस–के, कोलकाता; और डॉ. प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी। डॉ. बिनोदा मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापन किया और सम्मेलन का सार प्रस्तुत किया।

आसियान@50 और आसियान–इंडिया@25 पर आयोजित कोलकाता सम्मेलन में उपस्थित प्रतिभागी।

पूर्वोत्तर भारत का विकास और भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति

पृष्ठ 1 से जारी.....

स्थिति और भावी संभावनाएं; क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाएं विकसित करना; प्राकृतिक संसाधन, जल एवं ऊर्जा; शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यटन; और कनेक्टिविटी एवं भौतिक बुनियादी ढांचागत सुविधाएं।

परामर्श के दौरान समस्त प्रतिष्ठित प्रतिभागियों का यही मानना था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के साथ–साथ पड़ोसी देशों में भी स्वास्थ्य–देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, चिकित्सा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ–साथ चिकित्सा उपचार के उद्देश्य से पूर्वोत्तर से दूसरे देशों में जाने वाले कुल मानव संसाधन के बारे में पता लगाने के लिए एक अध्ययन कराया जा सकता है। उधर, पूर्वोत्तर राज्यों में लंबे समय से व्याप्त आपूर्ति पक्ष की खाई यानी किफायती सेवाएं मुहैया कराने वालों की कमी में सुधार की गुंजाइश का पता लगाया जा सकता है जो इसके पूरक के तौर पर काम करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए गांवों में भौतिक और आभासी (वर्चुअल) कनेक्टिविटी बेहतर करने पर अब फोकस किया जा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए वस्तुओं और सेवाओं के मामले में पूर्वोत्तर राज्यों से पड़ोसी देशों को व्यापार के रुख (पैटर्न) पर एक परामर्श या नीतिगत संक्षिप्त दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पूर्वोत्तर राज्यों से पड़ोसी देशों को कच्चे माल का निर्यात करने और वहां से तैयार उत्पादों का आयात करने के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए भी एक अध्ययन की आवश्यकता है।

एक विशेष सर्वेक्षण करने के लिए आयुष मंत्रालय को एक प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी पारंपरिक चिकित्सा को कैसे मजबूत किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापार सुगमता, लॉजिस्टिक्स (रसद) की लागत, जिला स्तरीय मानव विकास संकेतकों से जुड़े सांख्यिकीय आंकड़ों आदि भी एक प्रारंभिक दस्तावेज पेश किए जाने का भी परामर्श दिया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी स्तरों पर विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक आर्थिक विकास से जुड़े मसलों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें सुलझाने के लिए संभावित उपाय लागू किए जाने चाहिए।

समापन सत्र में प्रो. ब्रज बिहारी कुमार, अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) ने समापन भाषण दिया। डॉ. केएच. पालिन, संस्थापक एवं प्रमुख, शिजा हॉस्पिटल्स, इम्फाल ने समापन सत्र में सभी का स्वागत किया। प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने सम्मेलन की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बाद श्री शेषाद्रि चारी, सदस्य, संचालन परिषद, आरआईएस और रणनीतिक एवं विदेश नीति विश्लेषक एवं पत्रकार, ने विशेष भाषण दिया। समापन भाषण प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, ने दिया और सुश्री धृति गोगोई, आरजीवीएन सोसायटी, ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

वैश्विक उत्पादन नेटवर्कों में आईबीएसए देशों की भागीदारी

सुश्री गरिमा धीर, आईबीएसए फेलो, आरआईएस में प्रस्तुति दी। 5 दिसंबर 2017 को आरआईएस में एक नाश्ता संगोष्ठी (ब्रेकफास्ट सेमिनार) में प्रस्तुति दी। डॉ. अश्विनी गुप्ता, वैज्ञानिक 'जी', वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस संगोष्ठी की अध्यक्षता की।

इस दौरान दी गई प्रस्तुति में वैश्विक उत्पादन नेटवर्कों में आईबीएसए देशों की भागीदारी के रुझान, स्वरूप और क्षमता का विश्लेषण किया गया। इन देशों द्वारा किए जाने वाले नेटवर्क उत्पादों के निर्यात का अवलोकन करके यह विश्लेषण किया गया, जो विनिर्माण के अंतर्गत एक उप श्रेणी है और जिसके तहत वैश्विक उत्पादन नेटवर्क अत्यंत प्रमुख होते हैं।

इस दौरान क्रमशः तीन आईबीएसए देशों में आर्थिक स्थितियों और औद्योगीकरण के स्वरूप का व्यापक अवलोकन भी किया गया। विश्लेषण से यह पता चला कि तीनों अर्थव्यवस्थाएं अपने यहां औद्योगिक क्षेत्र के विकास के मामले में एक जैसी नहीं हैं और इनमें प्रत्येक देश को विविध आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

हालांकि, इन भिन्नताओं के बावजूद ये सभी तीनों राष्ट्र अपने यहां विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देने की आकांक्षा रखते हैं। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि उत्पादन नेटवर्कों में और भी अधिक मजबूती के साथ भाग लिया जाए।

इसे ध्यान में रखते हुए सुश्री धीर ने वैश्विक उत्पादन नेटवर्कों में आईबीएसए देशों की भागीदारी पर एक विश्लेषण प्रदान किया। यह भी बताया गया कि उत्पादन नेटवर्कों में इन तीनों आईबीएसए देशों की भागीदारी अपेक्षा से कम रही है। उदाहरण के लिए, ब्राजील के कुल निर्यात में नेटवर्क निर्यात की हिस्सेदारी वर्ष 2015 में महज 6 प्रतिशत ही थी। यही हिस्सेदारी भारत के कुल निर्यात में 9 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका के कुल निर्यात में 16 प्रतिशत थी। इसके विपरीत, चीन और वियतनाम के कुल निर्यात में नेटवर्क उत्पादों की हिस्सेदारी क्रमशः 41 प्रतिशत और 37 प्रतिशत थी। हालांकि, सापेक्ष दृष्टि से आईबीएसए समूह चीन के आकार का 0.6 गुना (जीडीपी के संदर्भ में) है, जबकि आईबीएसए समूह का नेटवर्क उत्पाद निर्यात चीन के नेटवर्क उत्पाद निर्यात का महज 0.06 ही है। इसके बावजूद इन देशों में वैश्विक उत्पादन नेटवर्कों के साथ एकीकृत होने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। हालांकि, इसे सुनिश्चित करने के लिए आईबीएसए देशों को व्यापार एवं लेन–देन की लागत में कमी करने और अपने यहां बुनियादी ढांचागत बाधाओं को दूर करने के लिए सख्ती से काम करना होगा।

चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच और व्यापार एवं स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून

आरआईएस भी भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिल्ली में 21 से 23 नवंबर 2017 तक सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे के संदर्भ में 'चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच और व्यापार एवं स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून' पर आयोजित प्रथम विश्व सम्मेलन का एक सह–प्रायोजक था। आरआईएस ने एसडीजी के संदर्भ में चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच और स्वास्थ्य पर एक स्थिति प्रपत्र भी तैयार किया है। आरआईएस ने इसके साथ ही सम्मेलन के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) पर विवरणिका (ब्रोशर) भी तैयार किया।

दसवाँ दक्षिण.....

पृष्ठ 7 से जारी.....

पर और अधिक सफल क्षेत्रीय एकीकरण परियोजनाओं से सबक लेकर इस निकाय में नई जान फूंकने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह उल्लेख किया गया कि विभिन्न देश उप–क्षेत्रीय और पार–क्षेत्रीय (ट्रांस–रीजनल) पहलों की ओर उन्मुख हो रहे हैं, इसलिए क्षेत्रीय एकीकरण को उसकी संपूर्णता में बढ़ावा देने के लिए उनसे लाभ उठाने हेतु पर्याप्त अवसर हैं। किसी क्षेत्र के भीतर निवेश के प्रवाह के संदर्भ में यह उल्लेख किया गया कि एकीकरण (कच्चे माल की आपूर्ति एवं वितरण पर नियंत्रण करने और किसी संबंधित व्यवसाय का अधिग्रहण करने संबंधी दोनों ही तरीकों से) के लिए व्यापक अवसर मौजूद हैं। इसके लिए पूरक नीतियों की आवश्यकता है, ताकि नीतिगत बाधाओं को दूर किया जा सके। इस दौरान सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), किसानों के अधिकारों के संरक्षण के परिप्रेक्ष्य से पौधे एवं आनुवांशिक संसाधनों के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों के गवर्नेंस, नवाचारों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लघु एवं मध्यम उद्यमों पर भी विस्तृत चर्चाएं हुईं।

दक्षिण–दक्षिण सहयोग को सीखना–समझना

आरआईएस संकाय के सदस्यों के साथ उपस्थित हैं दक्षिण–दक्षिण सहयोग सीखने–समझने पर आयोजित आईटीईसी कार्यक्रम के प्रतिभागी।

दक्षिण–दक्षिण सहयोग को सीखने–समझने पर एक क्षमता–निर्माण कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के आईटीईसी/एससीएएपी कार्यक्रम के तहत 13 से 24 नवंबर 2017 तक आरआईएस, नई दिल्ली, में आयोजित किया गया जिसमें 22 विभिन्न दक्षिणी या विकासशील देशों के 29 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान विकास सहयोग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण ों से संबंधित पदस्थ लोगों को अवगत कराया गया और इसके साथ ही विकास सहयोग पर मापदंडों; सैद्धांतिक पृष्ठभूमि; विकास संविदाः रूपात्मकता; एसएससी से जुड़े विभिन्न कर्ताओं; एसएससी में भारत की भूमिकाः एक क्षेत्रवार परिप्रेक्ष्य और एसएससी के लिए वैश्विक अवसरों एवं एसएससी का आकलन करने के मार्ग में मौजूद चुनौतियों आदि मुद्दों पर गहन चर्चा हुई।

प्रतिभागियों में दुनिया के विभिन्न देशों और क्षेत्रों से आए अन्य लोगों के अलावा विविध समूह शामिल थे जिन्हें शैक्षणिक, कूटनीति में व्यापक विशेषज्ञता प्राप्त थी। आंतरिक और बाहरी दोनों ही विशेषज्ञों ने विविध विषयों जैसे कि सैद्धांतिक रूपरेखा एवं क्षमता निर्माण संबंधी अनुभवों, व्यापार एवं निवेश के मुद्दों, विकास वित्त और विकासशील देशों के नजरिए से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर अपने–अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान भारतीय संस्कृति, इतिहास एवं दर्शन के अलावा स्वास्थ्य तथा शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, निजी क्षेत्र एवं सीएसओ की भूमिका से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम रखने में भारत के योगदान पर क्षेत्रवार पहलुओं को भी प्रस्तुत किया गया। प्रतिभागियों की शैक्षणिक यात्रा के एक हिस्से के रूप में उनके लिए तिलोनिया स्थित बेयरफुट कॉलेज जाने और भारत की संसद को देखने के लिए भी एक यात्रा आयोजित की गई थी। इस दौरान प्रतिभागियों ने 'सौर मांओं' से बातचीत की जो विभिन्न देशों की नागरिक थीं और इस केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थीं। उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान विकास सहयोग से संबंधित अपने देश की पहलों और अनुभवों के बारे में भी जानकारी दी।

राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 2018.....

पृष्ठ 2 से जारी.....

व्यापार, निवेश एवं प्रौद्योगिकी पर आयोजित प्रथम सत्र की अध्यक्षता श्री एस. टी. देवारे, अध्यक्ष, अनुसंधान सलाहकार परिषद, आरआईएस ने की जिसमें लघु द्वीप विकासशील देशों (एसआईडीएस) पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस सत्र के प्रमुख वक्ता थेः राजदूत वीरेंद्र गुप्ता, नई दिल्ली; डॉ. एस.के. मोहंती, प्रोफेसर, आरआईएस; प्रोफेसर आराधना अग्रवाल, भारतीय अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन विभाग, कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल; सुश्री साक्षी उनियाल, फ्लेम विश्वविद्यालय, पुणे (पुणे के फ्लेम विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉ. आर. जी. नांबियार का प्रतिनिधित्व किया); श्री अरविंद गुप्ता, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन; श्री पारस टंडन, स्वतंत्र विश्लेषक। सुश्री रुचिता बेरी, सीनियर रिसर्च एसोसिएट, आईडीएसए और प्रो. शाहिद अहमद, प्रोफेसर एवं प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया के सह–पैनलिस्ट थे।

एसडीजी, महिला और सिविल सोसायटी पर आयोजित दूसरे सत्र की अध्यक्षता राजदूत अमर सिन्हा, विशिष्ट फेलो, आरआईएस, ने की। प्रो. अनुराधा चेनॉय, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू; डॉ. बालाकृष्ण पिसुपति, पूर्व कुलपति, ट्रांस डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी और श्री कौस्तुव बंद्योपाध्याय, निदेशक, एशिया में भागीदारी अनुसंधान मुख्य वक्ता थे। श्री अमिताभ बेहर, कार्यकारी निदेशक, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया; प्रो. गुलशन सचदेवा, यूरोपीय अध्ययन केंद्र, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू इस अवसर पर सह–पैनलिस्ट थे।

राजदूत अमर सिन्हा, विशिष्ट फेलो, आरआईएस, ने समापन सत्र की भी अध्यक्षता की। श्री जयदीप बिस्वास, कार्यवाहक प्रमुख, डीएफआईडी इंडिया एवं प्रो. एस. के. मोहंती, आरआईएस, ने समापन सत्र में संबोधन किया और इसके बाद प्रतिभागियों की ओर से अत्यंत सक्रियतापूर्वक चर्चा हुई।

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

- नई दिल्ली में 5 अक्टूबर 2017 को नीति आयोग द्वारा आयोजित न्यू इंडिया@75 के लिए विकास एजेंडे की तैयारी हेतु 'क्षेत्रीय विकास–पूर्वोत्तर' पर आयोजित विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 6 अक्टूबर 2017 को 'भारत को वर्ष 2022 तक रूपांतरित करने के लिए सिफारिशें तैयार करने' के विषय पर नीति आयोग द्वारा आयोजित प्रबुद्ध मंडलों के साथ उच्चस्तरीय परामर्श में भाग लिया।
- मणिपाल में 7 अक्टूबर 2017 को मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थांन द्वारा आयोजित मणिपाल सम्मेलन 2017 में 'विज्ञान और समाज पर उभरते प्रतिमान' विषय पर छात्र समुदाय को संबोधित किया।
- 10 अक्टूबर 2017 को आईआईएफटी, नई दिल्ली में 'राष्ट्रीय एसएंडटी प्रणाली में उभरते एवं समकालीन अनुसंधान और विकास तथा नवाचार संकेतक और नीतिगत निहितार्थ' पर डीएसटी प्रायोजित अध्ययन के लिए एलपीएसी की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की।
- नई दिल्ली में 14 अक्टूबर 2017 को रामभाऊ माल्गी प्रबोधिनी और हिमालयन यूनीवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर भारत को रूपांतरित करने पर 'पूर्वोत्तरः दक्षिण पूर्व एशिया का द्वार' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में पैनलिस्ट थे।
- नई दिल्ली में 16 अक्टूबर 2017 को नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय और डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से 'गवर्नेंस में मील के पत्थर और राष्ट्रीय सुरक्षा 2014– 2017' पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में 'भारत के सशक्त विकास की ओर' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 16 अक्टूबर 2017 को 'विजन 2022: बाजार का आकार तीन गुना बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का क्षितिज चौड़ा करना' विषय पर आयुष मंत्रालय और सीआईआई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित उद्योग सम्मेलन में 'ब्रांड आयुर्वेद बनाना' विषय पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे।
- नई दिल्ली में 26 अक्टूबर 2017 को ओआरएफ द्वारा 'ब्रिक्स का भविष्यः अवसर और आने वाली चुनौतियों' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 27 अक्टूबर 2017 को नीति आयोग द्वारा आयोजित एसडीजी के कार्यान्वयन पर कार्यबल की बैठक में एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 30 अक्टूबर 2017 को ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रिकल्चरल साइंसेज (टीएएएस) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा संयुक्त रूप से 'छोटी जोत वाले किसानों के लिए विकास में मददगार नवाचारों हेतु प्रोत्साहन और रणनीतियां' पर आयोजित नीतिगत संवाद में 'नवाचारों के लिए प्रोत्साहन और नीतियों' पर एक प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 1 नवंबर, 2017 को सीआईआई द्वारा आयोजित सीआईआई अफ्रीका समिति 2017–18 की पहली बैठक में एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 2 नवंबर 2017 को कार्नेगी इंडिया, इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन (आईडीएफ) और बौद्धिक संपदा केंद्र (सीआईपी) द्वारा संयुक्त रूप से 'बौद्धिक संपदा अधिकार और भारत के अभिनव परिदृश्यं' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में 'नवाचार और बहुआयामी नीति बनाने' पर विशेष भाषण दिया।
- बेंगलुरू में 3 नवंबर 2017 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएएस) द्वारा आयोजित प्रौद्योगिकी–आधारित नवाचार नीति बनाने के लिए राष्ट्रीय पैनल की पहली बैठक में भाग लिया।
- यांगून में 11 नवंबर 2017 को भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान (आईएससीएस) और म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (एमआईएसआईएस) द्वारा 'आशा करना : भारत–म्यांमार संबंध' पर संयुक्त रूप से आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 'भारत–म्यांमार व्यापार और अन्य आर्थिक संबंधों की विस्तृत होती सीमाएं: रुझान, मुद्दे और आगे की राह' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- औरंगाबाद में 17 नवंबर, 2017 को एएसईआर केंद्र द्वारा आयोजित प्रथम उपचारात्मक कार्यक्रम टीएआरएल (सही स्तर पर शिक्षण) पर कार्यशाला में 'सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में भारतीय दृष्टिकोण और अन्य देशों के अनुभव से सीखना' विषय पर छात्रों को संबोधित किया।
- बॉन में 20 नवंबर 2017 को डीआईई, जीडीआई और एमजीजी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'एमजीजी पूर्व छात्र और भागीदार सम्मेलन 2017 – वैश्विक न्याय और सामाजिक सामंजस्यः 2030 एजेंडे की प्रमुख चुनौतियों' के दौरान 'उभरती शक्तियां और संयुक्त राष्ट्रः वैश्विक न्याय एवं सामाजिक एकता का मामला' विषय पर आयोजित सत्र में चर्चाकर्ता थे।
- बॉन में 20 नवंबर 2017 को जीडीआई द्वारा 'टी20 प्रक्रिया और थिंक टैंक नेटवर्कों की भूमिका' पर आयोजित कार्यशाला में 'टी20 के दीर्घकालिक असर और निरंतरता में सुधार' पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे।
- बॉन में 22 नवंबर 2017 को डीईई, जीडीआई और एमजीजी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'एमजीजी पूर्व छात्र और भागीदार सम्मेलन 2017– वैश्विक न्याय और सामाजिक सामंजस्यः 2030 एजेंडे की प्रमुख चुनौतियों' के दौरान '2017 में टी20 और टी20 अफ्रीकाः उपलब्धियां और आगे की राह' पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे।
- नई दिल्ली में 23 नवंबर 2017 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,

भारत में डब्ल्यूएचओ के कंट्री ऑफिस और अंतर्राष्ट्रीय कानून की भारतीय सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के संदर्भ में 'चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच और व्यापार एवं स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून' पर आयोजित प्रथम विश्व सम्मेलन के दौरान 'स्वास्थ्य उत्पाद को प्रभावित करने वाले डब्ल्यूटीओ व्यापार समझौतों–संदर्भ एसडीजी' पर आयोजित सत्र और 'समीक्षा सत्र' की अध्यक्षता की।

- पेरिस में 24 नवंबर 2017 को ओईसीडी द्वारा 'प्रभावकारी विकास सहयोग की एक साझा समझ की ओर: विभिन्न कर्ताओं और दृष्टिकोणों से सीखने' पर आयोजित अनौपचारिक आदान–प्रदान के दौरान 'एसडीजी के लिए अग्रसर: समावेशी संवाद और ज्ञान का आदान–प्रदान: विभिन्न तौर–तरीकों में सहयोग की ताकत को तलाशने' पर एक प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 1 दिसंबर 2017 को नीति आयोग द्वारा आयोजित 'एसडीजी 2 हासिल करने में विचारों के आदान–प्रदान के लिए बैठक' में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 5 दिसंबर, 2017 को आयुष मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की) और फार्मेक्सिल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य 2017 – आयुष एवं वेलनेस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन' के पहले संस्करण में 'एक ब्रांड रणनीति बनाना: विश्व के लिए आयुष की उपचार शक्ति' पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे।
- 5 दिसंबर 2017 को इस्लामाबाद में सतत विकास नीतिगत संस्थान (एसडीपीआई) द्वारा आयोजित 'विकास के सत्तर वर्ष : आगे की राह' पर आयोजित बीसवें सतत विकास सम्मेलन के दौरान 'दक्षिण एशिया में संरचनात्मक विषमता: मुद्दे, चुनौतियां और नीतिगत समाधान' पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे (स्काइप द्वारा)।
- नई दिल्ली में 12 दिसंबर 2017 को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 'आसियान–भारत कनेक्टिविटी शिखर सम्मेलन 2017: 21वीं सदी में एशिया के लिए डिजिटल और भौतिक संपर्कों को नई मजबूती प्रदान करने' के दौरान 'कनेक्टिविटी का निर्माण करना: ऋण व्यवस्था' पर आयोजित सत्र का संचालन किया।
- नई दिल्ली में 13 दिसंबर 2017 को एनसीएईआर और जेआईसीए द्वारा संयुक्त रूप से 'जेआईसीए देश विश्लेषण पत्र 2017 ' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 14 दिसंबर 2017 को नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय द्वारा 'क्षेत्रीयवाद और वैश्वीकरण: पूरकताएं और प्रतिवाद' पर आयोजित सम्मेलन के दौरान 'अर्थशास्त्र और व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय परस्पर क्रिया' पर एक प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 20 दिसंबर 2017 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएएस) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैम्पस, बेंगलुरू द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'प्रौद्योगिकी–आधारित नवाचार नीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय पैनल' की दूसरी बैठक में एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- जोधपुर में 27 दिसंबर 2017 को भारतीय आर्थिक संघ द्वारा आयोजित शताब्दी वार्षिक सम्मेलन–2017 में 'बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के भविष्य' पर मुख्य भाषण दिया (अनुपस्थिति में)।

प्रो. एस. के. मोहंती

- 14–18 अक्टूबर 2017 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हिंद महासागर रिम संघ (आईओआरए) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष (दक्षिण अफ्रीका) द्वारा आयोजित हिंद महासागर रिम शैक्षणिक समूह (आईओआरएजी) एवं वरिष्ठ अधिकारियों की समिति (सीएसओ) की 23वीं बैठक, मंत्रिपरिषद (सीओएम) की 17वीं बैठक में भाग लेने और 'मत्स्य पालन के आर्थिक पहलुओं: आईओआरए में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा' पर प्रस्तुति देने हेतु भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा नामित किए गए।
- 3 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा 'भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (सीईसीपीए)' पर पेश की गई रिपोर्ट पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 14 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आईओआरए के सदस्य देशों से भारत आए 21 पत्रकारों/मीडिया कर्मियों के लिए 12 से 17 नवंबर, 2017 तक आयोजित परिचय कार्यक्रम में भाग लिया।
- 16 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में आईसीडब्ल्यूए द्वारा आयोजित हिंद महासागर पर तीसरे ऑस्ट्रेलिया–भारत–इंडोनेशिया त्रिपक्षीय संवाद (टीडीआईओ) पर हुई परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 21 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में आईसीडब्ल्यूए द्वारा आयोजित हिंद महासागर पर तीसरे ऑस्ट्रेलिया–भारत–इंडोनेशिया त्रिपक्षीय संवाद (टीडीआईओ) के दौरान 'हिंद महासागर में मत्स्य पालन का प्रबंधन: गहरा और करीबी सहयोग स्थापित करना' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 22 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा विश्व व्यापार संगठन के 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए भारत की प्राथमिकताओं पर आयोजित परामर्श बैठक में भाग लिया।
- 24 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित परिचर्चा बैठक में 'व्यापार और निवेश में एलएसी देशों के साथ भारत की साझेदारी' पर एक प्रस्तुति दी।

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

- 5 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली में आईसीडब्ल्यूए द्वारा आयोजित भारत और रूस के थिंक–टैंकों के प्रमुखों (हॉट) की दूसरी बैठक 2017 के दौरान 'यूरेशिया और भारतः अवसर और चुनौतियां (ईएईयू और एससीओ में भारत की सदस्यता के साथ)' पर आयोजित सत्र में 'भारत और ईएईयू के बीच उभरते आर्थिक संबंध : यूरेशिया के साथ सीएसओ के एकीकरण के निहितार्थ' पर एक प्रस्तुति दी।
- 8 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा श्रीलंका के साथ प्रस्तावित आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ईटीसीए) के तहत वार्ताओं पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 16 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली में पीएचडी चैंबर द्वारा आयोजित पीएचडी चैंबर की विदेश व्यापार और निवेश समिति पर परिचर्चा बैठक में एक विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में भाग लिया।
- 26 दिसम्बर 2017 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग में 'भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (सीईसीपीए)' रिपोर्ट पर आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया।

प्रो. टी. सी. जेम्स

विजिटिंग फेलो

- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा गठित आईपीआर चेयर समीक्षा समिति के सदस्य समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 13 अक्टूबर 2017 को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को सौंपी।
- 27 अक्टूबर 2017 को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अधिकारियों के लिए आईपीआर पर प्रशिक्षण कक्षा आयोजित की।
- 24 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में स्टार्ट–अप्स, नवाचार और बौद्धिक संपदा पर मुख्य वक्ता थे।
- 25 नवंबर, 2017 को दिल्ली न्यायिक अकादमी में दिल्ली के न्यायिक अधिकारियों के लिए आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम में भौगोलिक संकेतों, व्यापार संबंधी राज और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण पर सार्वजनिक हित बनाम निजी अधिकार और विधिशास्त्र संबंधी घटनाक्रमों पर व्याख्यान दिया।
- 13 दिसंबर 2017 को बेंगलुरू में नीतिगत अनुसंधान के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र विभाग, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अभिनव नीतिगत अनुसंधान पर कार्यशाला (डब्ल्यूएसटीआईपीआर) में 'बौद्धिक संपदा अधिकारः भारतीय परिदृश्य, चुनौतियों और अवसरों' पर व्याख्यान दिया।
- 27 दिसंबर 2017 को मन्नूती, त्रिशूर में केरल कृषि विभाग द्वारा भौगोलिक संकेत के रूप में मारयूर गुड़ के संरक्षण पर आयोजित उच्चस्तरीय परामर्श में एक विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया।

डॉ. प्रियदर्शी दाश

रिसर्च एसोसिएट

- 12–14 अक्टूबर, 2017 को एफआईएनएस मुंबई द्वारा गोवा, भारत में समुद्री सुरक्षा पर आयोजित सागर संवाद 1.0 के दौरान 'हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार और निवेशः आईओआरए से नीली अर्थव्यवस्था पर सबक' के बारे में एक प्रस्तुति दी।
- 9 नवंबर, 2017 को स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित 'विश्व व्यापार संगठन में उभरते मुद्दों' पर गोलमेज सम्मेलन में मत्स्य पालन सब्सिडी पर भाषण दिया।
- 14–16 नवंबर, 2017 के दौरान काठमांडू में आयोजित दसवें दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन में व्यापार सुविधा और कनेक्टिविटी पर हुए विशेष सत्र में एक पैनलिस्ट के रूप में भाषण दिया।
- 24–25 नवंबर, 2017 को वियतनाम के न्हा ट्रांग में आयोजित नीली अर्थव्यवस्था पर आसियान–भारत कार्यशाला में 'नीली अर्थव्यवस्था को विकसित और सुदृढ़ करनाः भारत और क्षेत्र' पर एक प्रस्तुति दी।
- 15–17 दिसंबर, 2017 को चीन के नैननिंग में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशियाई सहयोग अंतर्राष्ट्रीय फोरम 2017 में बीआरआई और एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर पहल के बीच गठबंधन पर आयोजित कार्यशाला में चर्चाकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कीं और 'भारत की क्षेत्रीय एकीकरण पहलों' पर एक प्रस्तुति दी।

डॉ. सब्यसाची साहा

सहायक प्रोफेसर

- 12–13 अक्टूबर 2017 को रूस के मॉस्को में 'रूस–भारत संबंधों के रणनीतिक विजन और विश्व व्यवस्था में परिवर्तनों' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और ब्रिक्स को मजबूत बनाने एवं तकनीकी आधुनिकीकरण की द्विपक्षीय रणनीति पर एक प्रस्तुति दी।
- 9 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा विश्व व्यापार संगठन पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और ई–कॉमर्स से जुड़े मुद्दों पर एक प्रस्तुति दी।
- 5–6 दिसंबर 2017 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषदों के वैश्विक फोरम की तीसरी बैठक के दौरान 'एसटीआई और एसएमई' पर आयोजित सत्र में पैनल के सदस्य के रूप में भाग लिया।

नवीनतम प्रकाशन

रिपोर्ट

भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय सहयोग (आईएमटी–टीसी): एक मजबूत आसियान–भारत साझेदारी की ओर

एआईसी – आरआईएस, नई दिल्ली, 2017

दक्षिण–दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग: महत्वपूर्ण आइडिया

आरआईएस, नई दिल्ली, 2017

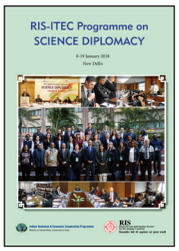

विज्ञान कूटनीति पर आरआईएस–आईटीईसी कार्यक्रम

आरआईएस, नई दिल्ली, 2017

आरआईएस प्रकाश बिंदु (स्पॉटलाइट) सभी के लिए आवास

आरआईएस, संख्या 1, नई दिल्ली, 2017

आरआईएस का परिचर्चा पत्र

#219 **एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर में आपसी जन साझेदारी: ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध** द्वारा वी. सेल्वाकुमार

#218 **मानव संसाधन विकास में एशिया–अफ्रीका सहयोग** द्वारा संतोष मेहरोत्रा

#217 **एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर में व्यापार सुविधा : अफ्रीका में भारत–जापान सहयोग की संभावनाएं** द्वारा एस.के. मोहंती, प्रियदर्शी दाश, वैभव कौशिक और भास्कर कश्यप

#216 **अर्थव्यवस्था में महिलाएं: एशिया–अफ्रीका क्षेत्र में विकास के लिए एक अप्रयुक्त संसाधन** द्वारा रेनाना झाबवाला

#215 **एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर में स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग** द्वारा हरप्रीत संधू

#214 **अफ्रीका में कौशल विकास: एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर में भारत–जापान सहयोग की गुंजाइश** द्वारा मनमोहन अग्रवाल

#213 **एशिया–अफ्रीका विकास कॉरिडोर में आपसी जन साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत–जापान सहयोग** द्वारा रुचिता बेरी

#212 **मौद्रिक नीति: इसके बदलते उद्देश्य, साधन और परिणाम** द्वारा मनमोहन अग्रवाल और इरफान शाह

#211 **फर्म की निर्यात क्षमता में वित्तीय पहुंच और वित्तीय विकास की भूमिका : एशिया प्रशांत से अनुभवजन्य साक्ष्य** द्वारा दुरइराज कुमारसामी और प्रकाश सिंह

जर्नल

एशियाई जैव प्रौद्योगिकी और विकास की समीक्षा

खंड 19 संख्या 2, जुलाई 2017

आरआईएस नीतिगत संक्षिप्त

#79 **अफ्रीका में भारत और जापान के लिए रणनीतिक अवसर: एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर (एएजीसी) पहल** द्वारा मुकुल आशेर और महालक्ष्मी गणपति, दिसंबर 2017

आरआईएस डायरी

खंड 13 संख्या 4, अक्टूबर 2017

आरआईएस संकाय द्वारा बाह्य प्रकाशनों में योगदान

चतुर्वेदी, सचिन और सब्यसाची साहा. 2017. 'वैश्विक गवर्नेंस की प्रतिस्पर्धात्मक अनिवार्यताएं और ब्रिक्स के अंतर्गत राष्ट्रीय हित: एक भारतीय परिप्रेक्ष्य।' *राइजिंग पावर्स त्रैमासिक*, खंड 2 संख्या 3, अगस्त।

चतुर्वेदी, सचिन और सब्यसाची साहा. 2017. ''वैश्विक गवर्नेंस की प्रतिस्पर्धात्मक अनिवार्यताएं और ब्रिक्स के अंतर्गत राष्ट्रीय हित: एक भारतीय परिप्रेक्ष्य।' *ओआरएफ सामयिक पेपर*, संख्या 136, दिसंबर।

चतुर्वेदी, सचिन. 2017. 'सरकार विकास को पटरी पर वापस लाने और अधिक नौकरियां सृजित करने के लिए क्या कर सकती है।' *द वीक*, अक्टूबर 07.

चतुर्वेदी, सचिन. 2017. श्रीलंका का आर्थिक भविष्य: मजबूत विकास की गारंटी। *डेली न्यूज*, अक्टूबर 16.

चतुर्वेदी, सचिन. 2017. पूर्वोत्तर क्षेत्र में आगे की राह तलाशना। *द वीक*, नवंबर 13.

नवीनतम प्रकाशन

चतुर्वेदी, सचिन. 2017. 'बौद्धिक संपदा अधिकार, नवाचार, और भारत के लिए चावल रणनीति।' समरेन्द्र मोहंती (संपादक) *भारत के लिए भावी चावल रणनीति*। एकेडेमिक प्रेस।

चतुर्वेदी, सचिन. 2017. 'भारत के सशक्त विकास की ओर' बिबेक देबरॉय और अशोक मलिक (संपादक) *India @ 70 Modi @ 3.5 : नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में हो रहे व्यापक बदलावों से रू–ब–रू होना* नई दिल्ली: विज्डम ट्री।

डे, प्रबीर. 2017. 'दक्षिण एशिया में कनेक्टिविटी सहयोग: प्रमुख पहलों की समीक्षा। मुस्तफिजूर रहमान और फहमिदा खातून (संपादक) *2030 में दक्षिण एशिया की फिर से कल्पना करना*, नीतिगत संवाद केंद्र (सीपीडी), ढाका।

डे, प्रबीर. 2017. 'बीबीआईएन में सीमा पार से कागज रहित व्यापार को सुगम बनाना: एक प्रस्ताव।' डीपीजी गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट, खंड 2, अंक 6.

डे, प्रबीर. 2017. 'आसियान–भारत साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर जश्न।' *ऑन ट्रेड*, खंड 4, संख्या 1.

डैश प्रियदर्शी. 2017. 'दक्षिण एशिया में विकास का वित्तपोषण : रूढ़िवादी दृष्टिकोणों से परे' अक्टूबर 2015 में आयोजित दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन (एसएईएस) – 9 के सम्मेलन खंड के रूप में, नीतिगत संवाद केंद्र।

दुरइराज कुमारसामी और रेड्डी, के शिवा. 2017. 'मुद्रा की मांग एवं प्रभुत्व पर क्रेडिट कार्डों और डेबिट कार्डों का असर : भारत से साक्ष्य', *एकेडमी ऑफ एकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टडीज जर्नल*, खंड 21, संख्या 3.

आरआईएस में प्रतिनिधिमंडलों की अगवानी

- कृषि और इसकी विकास श्रृंखला से संबंधित मुद्दों पर एक संवादात्मक सत्र 1 नवंबर 2017 को श्री मार्कोस एस. जैंक, सीईओ, एशिया ब्राजील एग्रो एलायंस, सिंगापुर; श्री ब्रेनो हरमन, काउंसलर, ब्राजील का दूतावास, नई दिल्ली, और श्री रुई सैंटोस रोचा कामारगो, व्यापार अधिकारी, ब्राजील का दूतावास, नई दिल्ली के साथ।
- आरआईएस के कार्यकलाप पर एक संवादात्मक सत्र 8 नवंबर 2017 को ग्लोबस प्रतिनिधिमंडल के साथ जिसमें डॉ. हेलेन सजर्सन, ग्लोबस वैज्ञानिक समन्वय और अनुसंधान, यूरोपीय अध्ययन के लिए एरेना सेंटर में प्रोफेसर, नॉर्वे; डॉ. पंडी पिल्लई, विट्स स्कूल ऑफ गवर्नेंस में प्रोफेसर, दक्षिण अफ्रीका; डॉ. थॉमस डायज, टुबिंगन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, जर्मनी; डॉ. बेन टोन्रा, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में प्रोफेसर, आयरलैंड; प्रो. माइकल सी. डेविस, नेशनल एंडॉमेंट फॉर डेमोक्रेसी (संयुक्त राज्य अमेरिका) और जेओयू में फेलो; डॉ. इवॉर सरकिन्स्की, विट्स स्कूल ऑफ गवर्नेंस में वरिष्ठ व्याख्याता, दक्षिण अफ्रीका; डॉ. सोनिया लुकारेली, इटली के बोलोग्ना विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर; डॉ. माइया के. डेविस–क्रॉस, नॉर्थईस्टर्न यूनीवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर, संयुक्त राज्य अमेरिका; डॉ. निकोला टॉमिक, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में पोस्टडॉक्टोरल फेलो, आयरलैंड; डॉ. फ्रांजिस्कस वॉन लके, टुबिंगन विश्वविद्यालय में शोधकर्ता, जर्मनी और डॉ. एंटोनियो जोट्टी, बोलोग्ना विश्वविद्यालय में रिसर्च फेलो, इटली शामिल थे।
- एसडीजी से संबंधित मुद्दों पर एक संवादात्मक सत्र 5 दिसंबर, 2017 को श्री डेविड विलकॉक्स, रीच स्केल के संस्थापक, ब्रुकलिन मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, और सुश्री मीगन फैलोन, सीईओ, बेयरफुट कॉलेज इंटरनेशनल के साथ।
- एसडीजी, वैश्विक साझेदारियों और त्रिकोणीय सहयोग बातचीत 13 दिसंबर 2017 को श्री जेरोम पॉन्स, काउंसलर, हेड ऑफ कोऑपरेशन, यूरोपीय संघ, थाईलैंड संबंधी प्रतिनिधिमंडल और सुश्री सेसिलिया कोस्टा, अटैची, सहयोग प्रबंधन, भारत और भूटान में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ।

RIS
Research and Information System for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4–बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003, भारत । दूरभाष: 91–11–24682177–80
फैक्स: 91–11–24682173–74, ई–मेल: dgoffice@ris.org.in
वेबसाइट: http://www.ris.org.in

Follow us on:
www.facebook.com/risindia @RIS_NewDelhi www.youtube.com/RISNewDelhi

प्रबंध संपादक: तीश मल्होत्रा

पूर्वोत्तर का विकास और भारत की 'एक्ट–ईस्ट' नीति

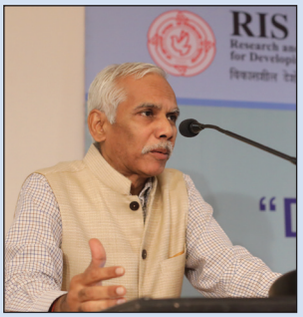

Jh uohu oek
lfpo] mÙkj ioh {k= fodkl e=ky;

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के एजेंडे के तहत अनेक विशिष्ट मसलों को सुलझाया जाना चाहिए। यह क्षेत्र समरूप या एक समान नहीं है। इसके अंतर्गत आने वाला प्रत्येक राज्य कई मापदंडों जैसे कि शहरीकरण के स्तर, प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद, और जातीय समुदायों की संख्या के मामले में दूसरे राज्य से भिन्न है। अतः पूर्वोत्तर के विकास का एजेंडा विशिष्ट क्षेत्रों पर व्यावहारिक सुझाव देने के संदर्भ में अवश्य ही कुछ इस तरह का होना चाहिए जिससे कि सीमा के दोनों ही ओर के क्षेत्रों को इसका लाभ मिले। इसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य विशिष्ट मुद्दों को सुलझाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में पहचाने गए मुद्दों में 'सीमा हाट' और लैंड कस्टम्स स्टेशन (एलसीएस) के समक्ष मौजूद समस्याओं के अलावा यह सवाल भी शामिल है कि आखिरकार यह क्षेत्र पड़ोसी देशों के लिए सस्ते कच्चे माल का स्रोत कैसे बन गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पादित होने वाले विभिन्न उत्पादों जैसे कि बांस, अनूठे फलों एवं सब्जियों, ऑर्किड और मसालों जैसे कि अदरक आदि की मांग पड़ोसी देशों में काफी है। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश फिलहाल कनाडा से दालों का आयात करता है, जिनका आयात निकट भविष्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र से किया जा सकता है। इसके लिए पूर्वोत्तर राज्यों में दाल मिलों की स्थापना करनी होगी। अन्य उदाहरण यह हैं कि सही नीति अपनाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र से सुअर के मांस (पोर्क) की अतिरिक्त आपूर्ति का निर्यात आसियान देशों, यहां तक कि चीन को भी किया जा सकता है।

दूसरी ओर, बेंगलुरू में बिकने वाले बांस उत्पादों को पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्राप्त करने के बजाय वियतनाम से आयात किया जाता है। इन उत्पोदों की आपूर्ति पूर्वोत्तर क्षेत्र से करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। वस्त्रों के मामले पर भले ही वियतनाम और बांग्लादेश प्रतिस्पर्धी देश हों, लेकिन इसके बावजूद पूर्वोत्तर क्षेत्र कपड़ा प्रौद्योगिकी में योगदान करके लाभ हासिल कर सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमाओं के आसपास हो रहे अनौपचारिक व्यापार को औपचारिक रूप देने की आवश्यकता है। पड़ोसी देश भारत द्वारा खड़ी की गई गैर–व्यापारिक बाधाओं (एनटीबी) से नाखुश हैं। आईटीईसी (भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग) कार्यक्रमों को पड़ोसी देशों के साथ शुरू किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें भारत द्वारा अपनाई गई व्यापार व्यवस्थाओं से अवगत कराया जा सके। पूर्वोत्तर राज्यों और पड़ोसी देशों द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकृत मानकों के आधार पर उत्पाद–परीक्षण प्रयोगशालाओं को पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी स्थापित किया जा सकता है। इस तरह की व्यवस्था हो जाने पर सीमा पार से अप्रमाणित उत्पादों जैसे कि अपरीक्षित स्वास्थ्य पेय के आयात पर भी विराम लग जाएगा।

भारत के दूसरे हिस्सों के साथ आंतरिक व्यापार और पड़ोसी देशों के साथ विदेश व्यापार दोनों में ही सुगमता के लिए रसद (लॉजिस्टिक्स) से जुड़ी चुनौती से पार पाना भी अत्यंत जरूरी है जिस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम (एनईएचएचडीसी) और पड़ोसी देशों के बीच साझेदारियों के जरिए हस्तशिल्प एवं हथकरघा को और अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि स्थानीय फैशन डिजाइनरों द्वारा तैयार किए गए महंगे हथकरघा उत्पादों और स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई जाने वाली हस्तशिल्प के लिए पूर्वी सीमाओं के पार बाजारों का पता लगाया जा सके। पूर्वोत्तर क्षेत्र को अपनी विशेष अवस्थिति (लोकेशन) के मामले में जो बढ़त हासिल है उसे देखते हुए भारत–आसियान कनेक्टिविटी के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में साहसिक, चिकित्सा और धार्मिक पर्यटन को काफी बढ़ावा मिल सकेगा। हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों से कनेक्टिविटी में भी काफी प्रगति हुई है जिसे और भी बेहतर करने की आवश्यकता है। इसके लिए कई नए उद्यमों पर कार्य जारी है। जहां तक रेल कनेक्टिविटी का सवाल है, यह ध्यान में रखना चाहिए कि नई रेल पटरियों में कुल निवेश का 30 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के ही खाते में गया है। यही नहीं, बड़ी लाइन (ब्रॉड गेज) को त्रिपुरा तक बढ़ा दिया गया है। हम यह परिकल्पना कर सकते हैं कि आगे चलकर कनेक्टिविटी भारत के इंफाल से लेकर म्यांमार के मंडाले तक और यहां तक कि उससे भी परे सुदूर–पूर्व की ओर बढ़ जाएगी। अंतर्देशीय जलमार्गों से दूरी काफी कम हो जाएगी, जिसके लिए रो–रो नौका जैसी सेवाओं का पता लगाया गया है।

यद्यपि पूर्वोत्तर क्षेत्र से पड़ोसी देशों तक उड़ानों की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अलग–अलग गंतव्यों के लिए उनकी आवृत्ति या बारंबारता बढ़ाने की आवश्यकता है। खेल और स्थानीय व्यंजनों के अलावा संगीत, लोक नृत्य, इत्यादि जैसी समकालीन प्रदर्शन कलाओं को भी लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है, ताकि वे विकास सहयोग में पूरक बन सकें। इस तरह के उपायों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर और सीमा पार पारस्परिक जन–संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी।

**असम के गुवाहाटी में 24–25 अक्टूबर, 2017 के दौरान 'पूर्वोत्तर भारत का विकास और भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीतिः तालमेल की तलाश' पर आयोजित क्षेत्रीय परामर्श में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, सचिव श्री नवीन वर्मा द्वारा दिए गए मुख्य भाषण पर आधारित है।*